



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—रूप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2004/माघ 8, 1925

No. 107]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2004/MAGHA 8, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2004

सं. 28 (आरडे-2003)/2002—2007

का.आ. 129(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 2002-2007 के पैरा 1.1 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यात और आयात नीति 2002-2007 (31.3.2003 तक यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

1. “विदेशों में मरम्मत किए गए माल का पुनः आयात” से संबंधित 2.22 को ठीक करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :

पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक, कल पुर्जे और सहायक उपकरण चाहे आयातित हों अथवा स्वदेशी जिनमें वे शामिल नहीं हैं जो निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण 2002-2007 में निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं, को मरम्मत, जाँच, टैक्नालोजी के उच्चकरण या मान्यकरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विदेश भेजा जा सकता है और उनका लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति के बिना पुनः आयात किया जा सकता है।

2. “उपहारों के निर्यातों” से संबंधित पैराग्राफ 2.32 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

माल, जिसमें खाद्य वस्तुएँ शामिल हैं जिसका मूल्य एक लाइसेंसिंग वर्ष में 5,00,000रुपए से अधिक न हो, उपहार के रूप में निर्यात की जा सकती है। फिर भी आई टी सी (एचएस) में निर्यातों के लिए दर्शाई गई प्रतिबंधित मदें खाद्य वस्तुओं को छोड़कर लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति के बिना उपहार के रूप में निर्यात नहीं की जाएंगी।

3. “अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात” से संबंधित पैरा 2.33 को ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

वारण्टी पुर्जे, चाहे स्वदेशी हों अथवा आयातित, स्लान्ट, उपकरण मशीनरी, ऑटोमोबाइल हों अथवा कोई अन्य माल जिनमें निर्यात और आयात मदों का आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण 2002-2007 में निर्यात के लिए प्रतिबंधित शामिल नहीं हैं, का मुख्य उपकरण के साथ अथवा बाद में लेकिन ऐसे माल की संविदा वारण्टी अवधि के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन निर्यात किया जा सकता है।

4. “मरम्मत किए गए माल के निर्यात” से संबंधित पैरा 2.38 को ठीक करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :

निर्यात और आयात मदों का आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण 2002-2007, में निर्यात के लिए प्रतिबंधित मदों को छोड़कर माल या हिस्से निर्यात करने पर और खराब, टूटे अथवा अन्यथा उपयोग के लिए अनुपयुक्त का मरम्मत के लिए आयात किया जा सकता है और बाद में पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे माल की इस संबंध में जारी सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति के बिना निकास की अनुमति होगी।

5. स्तर धारकों के लिए शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी से संबंधित आयात निर्यात नीति के पैराग्राफ 3.7.2.1 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। 31 मार्च, 2003 को घोषित निर्यात आयात नीति में की गई पहल के हिस्से के रूप में इस योजना की घोषणा की गई थी जिसका उद्देश्य विशेषकर निर्यात में क्रमिक वृद्धि को तेज करना और भारत को विश्व के अन्य देशों के लिए विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए प्रमुख आधार बनाना है। यह महसूस किया गया है कि स्तरधारक विशेष रूप से लघु क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण और व्यापक भूमिका निभाते रहेंगे, चूंकि अधिकतर लघु युनिटों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक सीधी पहुँच नहीं होगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्यात के मूल्य में क्रमिक वृद्धि के 10 प्रतिशत की दर से शुल्क मुक्त आयात हकदारी की अनुमति है जो वास्तविक प्रयोक्ता की पात्रता की शर्त के अधीन है, जिसे अन्तिम उत्पादन के लिए सहायक/संबद्ध विनिर्माताओं/कामगारों को सौंपा जा सकता है। चूंकि यह योजना, तेजी से बढ़ रहे स्तरधारकों के विशेष लाभ के लिए है अतः इसके लाभ 1 अप्रैल, 2004 से उपलब्ध होंगे।

एक नई पहल होने के कारण, व्यापार एसोसिएशनों/निर्यात संवर्धन परिषदों और विभिन्न निर्यातकों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें योजना के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण माँगा गया है। इसी समय सरकार को इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि निर्यात में वृद्धि करने के लिए बिना किसी महत्वपूर्ण प्रयास के अन्यों के निर्यात का श्रेय लेने के लिए कुछ स्तरधारक अपने निर्यात कारोबार में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं इस रूप में योजना के तहत केवल अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे दिशान्तरण/निर्यात में वृद्धि निर्यात में क्रमिक वृद्धि के संबंध में अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। ऐसा करना योजना का दुर्पर्योग करना है। इसे देखते हुए, योजना को कार्यान्वित करने के लिए खास मानदण्ड निर्धारित करना आवश्यक हो गया है।

उक्त निर्यात और आयात नीति के :-

उप पैराग्राफ (vii) के पश्चात, पैराग्राफ 3.7.2.1 के अध्याय 3 में, निम्नलिखित टिप्पणियों को जोड़ा गया है, अर्थात :-

“टिप्पणी - 1 :- निर्यात के मूल्य के परिकलन के प्रयोजन हेतु, निम्नलिखित आयातों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा अर्थात :-

- (i) आयातित वस्तुओं का पुनः निर्यात या ट्रान्सशिपमेन्ट के जरिए किया गया निर्यात
- (ii) एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपीआई योजनाओं के तहत परिचालित यूनिटों का निर्यात कारोबार या इनके द्वारा विनियमित उत्पाद और डीटीए यूनिटों के माध्यम से निर्यातित उत्पाद
- (iii) मान्य निर्यात (चाहे भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुआ है) और इसके से भुगतान
- (iv) सेवा निर्यात
- (v) एक स्तरधारक से दूसरे स्तरधारक को की गई आपूर्ति
- (vi) दूसरे स्तरधारक की ओर से पहले स्तरधारक का निर्यात निष्पादन, योजना के तहत हकदारी का पात्र नहीं होगा
- (vii) एक स्तरधारक को गैरस्तरधारक द्वारा की गई आपूर्ति या निर्यात निष्पादन (2003-2004 के किसी निर्यात निष्पादन करने वाले पर्याय निर्यातिक/विनिर्माता) यदि आवेदक और गैर स्तरधारक का संबंधित पिछले वर्षों के प्रत्यक्ष निर्यात कारोबार की तुलना में क्रमिक वृद्धि 25 प्रतिशत से कम है।
- (viii) किसी समूह के भीतर तथा जिस समूह में यह आता है, एक आवेदक द्वारा किया गया निर्यात, इसके क्रमिक वृद्धि का अलग-अलग 25 प्रतिशत होगा।

टिप्पणी - 2 :- किसी निर्यातिक द्वारा, निर्यात में क्रमिक वृद्धि किसी अन्य निर्यातिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।”

टिप्पणी - 3 :- सरकार के पास लोकहित में यह अधिकार है कि वह उन निर्यात उत्पादों को विनिर्दिष्ट करें जो क्रमिक वृद्धि/हकदार के परिकलन के पात्र नहीं होंगे। उसी तरह सरकार उन वस्तुओं की सूची को अधिसूचित करे जो स्कीम के तहत आयात के अनुमत नहीं किए जाएंगे।

टिप्पणी - 4 :- ये मार्ग दर्शन 1 अप्रैल, 2003 को या बाद में किए गए निर्यातों पर लागू होंगे।

टिप्पणी - 5 :- यह पात्रता शुल्क क्रेडिट की शर्तों पर होगी।

6. “सेवा प्रदायकों के लिए शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी” से संबंधित पैराग्राफ 3.8 का उप पैराग्राफ 3 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

सेवा प्रदायक (होटल से अन्यत्र) पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान उनके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की औसत का 10 प्रतिशत के बराबर शुल्क मुक्त

आयातों के पात्र होंगे। तथापि, होटल एक सितारा और ऊपर के हेरीटेज़ होटल की मान्यता प्राप्त है) विशिष्ट रेस्तराँ और पर्यटन क्षेत्र के अन्य सेवा प्रदायक जो भारत सरकार पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत हैं वे पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा औसत का 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क मुक्त आयात के पात्र होंगे। एक और दो सितारा होटलों और विशिष्ट रेस्तराँ के लिए, स्कीम के तहत हकदारी हेतु अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का ही परिकलन किया जाएगा। शुल्क मुक्त हकदारी का किसी पूँजीगत माल के आयात जिसमें कलपुर्जे, कार्यालय उपकरण और व्यावसायिक उपकरण, कार्यालय फर्नीचर और उपभोज्य के लिए उपयोग किया जाएगा तथापि कृषि और दुर्घट उत्पादों मोटर कार, खेल कूद में प्रयुक्त होने वाले वाहन और सभी उद्देश्यों के लिए वाहन के आयात की अनुमति इस हकदारी के मद्दे नहीं दी जाएगी।

हकदारी और माल अहस्तान्तरणीय होगा और केवल उन सेवा प्रदायकों को उपलब्ध होगा, जिनके पास पिछले एक/दो/तीन लाइसेंसिंग वर्षों में तीस लाख रुपए से अधिक कुल अर्जित विदेशी मुद्रा होगी।

7. अग्रिम लाइसेंसिंग से संबंधित पैराग्राफ 4.1.6 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

अग्रिम लाइसेंस की सुविधा उनको उपलब्ध होगी जो सभी या कुछ निविष्टियाँ निर्यातक को मुक्त आपूर्ति करते हैं। ऐसे मामलों में मूल्य संवर्धन की संगणना के लिए अन्य शुल्क मुक्त निविष्टियों के साथ मुक्त निविष्टियों के राष्ट्रीय मूल्य को हिसाब में लिया जाएगा। तथापि यदि सभी निविष्टियाँ मुफ्त सप्लाई की जाती हैं तो आवेदक नीति के पैरा 4.2.7 के प्रावधानों के लिए विकल्प चुनने की छूट होगी।

8. “वार्षिक अपेक्षाओं के लिए अग्रिम लाइसेंस” से संबंधित पैरा 4.1.7 के निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

अग्रिम लाइसेंस वास्तविक निर्यातों, मध्यस्थ आपूर्तियों और मान्य निर्यतों के लिए वार्षिक अपेक्षाओं के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं।

निर्यात सदन, व्यापार सदन, स्टार व्यापार सदन और सुपर स्टार व्यापार सदन वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम लाइसेंस के पात्र होंगे। फिर भी यदि स्तर धारक के पास व्यापारी निर्यातक के रूप में प्रमाणपत्र है तो वे भी वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम लाइसेंस के हकदार होंगे बशर्ते कि संगत लाइसेंस पर सहायक विनिर्माता के नाम के पृष्ठांकन के लिए सहमत हों।

इस योजना के तहत हकदारी पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में निर्यात की पोत पर्यन्त निशुल्क/रेल पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 200 प्रति तक होगी। ऐसे लाइसेंस का सकारात्मक मूल्य संवर्धन होना चाहिए।

9. शुल्क मुक्त प्रतिपूति प्रमाण-पत्र से संबंधित पैरा 4.2.3 और 4.2.4 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

4..2.3 : डी एफ आर सी केवल विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा अधिसूचित मानक निवेश उत्पाद मानदण्डों के अन्तर्गत माने वाले उत्पादों के लिए जारी किया जाएगा। तथापि मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के संबंध में जो वास्तविक

उपयोक्ता शर्तों के अधीन हो अथवा जहाँ निविष्टियाँ आयात पूर्व शर्तों पर अनुमत हैं अथवा सामान्य मानदण्डों के अधीन इंधन के आयात के लिए इन निविष्टियों हेतु वास्तविक उपयोक्ता की शर्तों के साथ डी एफ आर सी जारी किया जाएगा।

ऐसे मामलों में जहाँ मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों में एसेटिक एन्हाइड्राइड, एफेझीन और स्यूडो एफेझीन, का आयात अनुमत है डी एफ आर सी जारी किया जाएगा, बशर्ते कि ये मदै आयात मदों की सूची से विशेष रूप से हटा दी गई हो।

4.2.4 : शिपिंग बिलों में यथाउल्लिखित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के अनुसार निविष्टियों के आयात के लिए डी एफ आर सी जारी किया जाएगा। ऐसे लाइसेंसों की वैधता 18 महीनों की होगी। डी एफ आर सी और अथवा इसके मद्दे आयातित माल मुक्त हस्तान्तरणीय होगा। तथापि वास्तविक उपयोक्ता शर्तों पर डी एफ आर सी अथवा इसके मद्दे आयातित सामग्री मुक्त हस्तान्तरणीय नहीं होगी।

10. पैरा 4.2.7 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

4.2.7 माल का आयात, जिसमें वो माल भी शामिल है जो आई टी सी (एचएस) में प्रतिबंधित के रूप में उल्लिखित है परन्तु निषेधात्मक मदै शामिल नहीं है, मुक्त सप्लाई की गई मदै समय-समय पर राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति के बिना जॉबिंग प्रयोजन के लिए अनुमति दी जा सकती है।

इसी प्रकार, मरम्मत, रि-कन्फीशनिंग, रि-इंजीनीयरिंग, जॉच इत्यादि के लिए माल के आयात की अनुमति सीमा शुल्क अधिसूचना की शर्तों के अनुसार होगी यद्यपि आयातों के लिए माल निर्यात आयात नीति/आयात निर्यात मदों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रतिबंधित हो।

11. पैरा 4.3.5 का अन्तिम वाक्य हटा दिया गया है।

12. “ई पी सी जी स्कीम” से संबंधित पैरा 5.1 के अंत में निम्नलिखित उप पैरा जोड़ा जाता है :

ई पी सी जी योजना के तहत मौजूदा संयंत्र और मशीनों के लिए रपर्य, रिफ्रेक्ट्रीज, कैटालिस्ट और उपभोज्यों का भी आयात किया जा सकता है, तथापि मोटर-कारों, स्पोर्ट्स, यूटिलिटी वाहनों/सभी प्रयोजनों के लिए वाहनों के आयात की अनुमति उन होटलों, ट्रेवल एजेण्टों, टूर-आप्रेटरों या टूर ट्रान्स्पोर्ट आप्रेटरों को दी जाएगी जिनका विदेशी मुद्रा अर्जन चालू लाइसेंसिंग घर्ष या पिछले एक/दो/तीन लाइसेंसिंग वर्षों में 1.5 करोड़ रुपए है।

13. पैराग्राफ 5.1क को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

5.1क ई पी सी जी योजना के तहत मौजूदा संयंत्र और मशीनों के लिए रपर्य, रिफ्रेक्ट्रीज, कैटालिस्ट और उपभोज्यों का भी आयात किया जा सकता है। बचाए गए शुल्क के 8 गुणा के बराबर निर्यात शुल्क, निर्यात दायित्व लगाया जाएगा जिसे लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख से 8 वर्षों की अवधि में पूरा करना होगा।

14. “निर्यात दायित्व” से संबंधित पैराग्राफ 5.4(1) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है। (1) निर्यात दायित्व उन वस्तुओं का निर्यात करके पूरा किया जाएगा जिन्हें इस योजना के तहत आयातित पूँजीगत वस्तुओं का प्रयोग करके विनिर्मित या उत्पादित किया जा सकता है। निर्यात दायित्व उन वस्तुओं का निर्यात करके भी पूरा किया जा सकता है जिसके लिए ई पी सी जी लाइसेंस प्राप्त किया गया है, लाइसेंस धारक/निर्दिष्ट सहायक विनिर्माता(ओं) विक्रेताओं के विभिन्न विनिर्माण कारी यूनिटों में विनिर्मित या उत्पादित किया जा सकता है। इस योजना के तहत निर्यात दायित्व प्रक्रिया पुस्तक खण्ड (1) में उल्लिखित श्रेणियों के अलावा ऐसे ही उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में विनिर्माता द्वारा प्राप्त किए गए औसत निर्यात को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से निर्यात दायित्व अन्य वस्तुओं का निर्यात करके या उसी फर्म/कम्पनी या कम्पनी के समूह, जिसके पास ई पी सी लाइसेंस है, द्वारा सेवा प्रदान करके भी पूरा किया जा सकता है। तथापि ऐसे मामलों में ई पी सी जी योजना के तहत लगाया गया अतिरिक्त निर्यात दायित्व प्रतिस्थापित उत्पादों/सेवाओं के लिए पिछले तीन वर्षों में यूनिट द्वारा प्राप्त किए गए औसत निर्यात दायित्व के अनुसार है।

लाइसेंस धारक अधिशेष निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण के विकल्प को चुन सकता है जो स्कीम के तहत लागत बीमा भाड़ा मूल्य और अधिशेष निर्यात दायित्व के अनुपात में बचाये गये शुल्क का 8 गुना के आधार पर होगा।

ये सुविधाएं सभी लाइसेंसों पर केवल विनिर्माता निर्यातकों/सेवा प्रदायकों को उपलब्ध होगी जहाँ निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाई गई आवेदन की तारीख तक वैध है। इस संबंध में ऐसे मामलों में वैकल्पिक म्रद के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन की तारीख को और/या बचाये गये शुल्क पर आधारित निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण को ही ध्यान में रखा जाएगा।

15. पैराग्राफ 6.6 (क) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:
- अनुमोदन मिलने पर, विकास आयुक्त द्वारा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट को अनुमति पत्र/आशय-पत्र जारी किया जाएगा। उत्पाद शुरू करने के लिए अनुमति प9 की प्रारम्भिक वैधता अवधि तीन वर्ष होगी इसकी वैधता अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन और वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है, तथापि 1-4-2002 से पूर्व अनुमोदित प्रस्तावों पर 6 वर्ष के बाद अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा। अनुमति पत्र के विस्तार के लिए एक मानक प्रपत्र परिशिष्ट 14 आईएमएम में दिया गया है।

16. पैराग्राफ 6.7 (क) निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:
- भवन, संयंत्र और मशीनों में एक करोड़ रुपए और इससे अधिक के न्यूनतम निवेश वाली परियोजना की ई ओ यू योजना के तहत स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है। न्यूनतम निवेश यूनिट द्वारा उत्पाद शुरू करने पर देखा जाएगा। तथापि, यह मौजूदा यूनिटों और ई एच टी पी/एस टी पी/हस्तशिल्प/कृषि/पुष्पोत्पादन/ जलकृषि/पशुपालन/सूचना प्रोद्यौगिकी/ सेवाओं में यूनिटों और अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित अन्य क्षेत्रों के लिए

लागू नहीं होगा। सेवा क्षेत्रों में यूनिट स्थापित करने के लिए प्रस्तावों के अलावा (आर एण्ड डी, सॉटवेयर और आई टी सेवाएं या अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित अन्य कोई सेवा कार्यकलाप के अलावा) ई ओ यू योजना के तहत यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदनों को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 14-I में निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा 15 दिन के भीतर स्वीकृत या अस्वीकृत करना होगा।

17. पैराग्राफ 7.7(क) में कोष्ठक में शब्द “अलावा” के बाद शब्द “आर. खण्ड. डी” को शामिल किया जाएगा।
18. पैराग्राफ 7.11(क) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :
7.11(क) एसईजेड यूनिटें, एक एसईजेड यूनिट से दूसरी एसईजेड/ ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी यूनिट को, आंशिक रूप से संसाधित/ अर्द्ध विकसित माल और सेवाओं सहित, विनिर्मित माल हस्तांतरित कर सकती है। तथापि, एसईजेड की ट्रेडिंग यूनिटें, अन्य एसईजेड यूनिट से दूसरी एसईजेड/ ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी यूनिट को आयातित/ डीटीए से प्राप्त माल को बेच/ हस्तांतरित कर सकती हैं।
19. उप पैराग्राफ 8.2(च) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :-
(च) किसी परियोजना या प्रयोजन के लिए वस्तुओं की आपूर्ति, अधिसूचना जारी करके वित्त मंत्रालय ने शून्य सीमा शुल्क पर जिन वस्तुओं के आयात की अनुमति दी है।
20. पैराग्राफ 9.47(iv) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-
मुक्त विदेशी मुद्रा या भारतीय रूपए में निर्यात के लिए किए गए भुगतान से संबंधित भारत में ‘सेवा’ की आपूर्ति जिसे अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया भुगतान माना जाता।
इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2004

No. 28 (RE-2003)/2002—2007

S.O. 129(E).—In exercise of powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Paragraph 1.1 of the Export and Import Policy, 2002-2007, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments in Exim Policy, 2002-07 (as amended upto 31.3.2003):-

1. Paragraph 2.22 pertaining to “Re-import of goods repaired abroad” stands corrected to read as under:

Capital goods, equipments, components, parts and accessories, whether imported or indigenous, except those restricted for export in the ITC(HS) Classification of Export & Import items, 2002-2007, may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement of up-gradation or standardization of technology and re-imported without a licence/certificate/permission

2. Paragraph 2.32 pertaining to the “Export of Gifts” is amended as under:

Goods, including edible items, of value not exceeding Rs.5,00,000/- in a licensing year, may be exported as gift. However, items mentioned as restricted for exports in ITC(HS) shall not be exported as gift, without a licence/certificate/permission.

3. Paragraph 2.33 pertaining to “Export of Spares” stands corrected to read as under:

Warranty spares, whether indigenous or imported, of plant, equipment machinery, automobiles or any other goods, except those restricted for export in the ITC(HS) Classification of Export & Import items, 2002-2007, may be exported alongwith the main equipment or subsequently but within the contracted warranty period of such goods subject to approval of RBI.

4. Paragraph 2.38 pertaining to “Export of repaired goods” stands corrected to read as under:

Goods or parts, except those restricted for export in the ITC(HS) Classification of Export & Import items, 2002-2007, thereof on being exported and found defective, damaged or otherwise unfit for use may be imported for repair and subsequent re-export. Such goods shall be allowed clearance without a licence/certificate/permission and in accordance with customs notification issued in this behalf.

5. Attention is invited to Para 3.7.2.1 of Exim Policy relating to Duty Free Credit Entitlement for Status Holders. The Scheme was announced as part of the initiatives taken in the Exim Policy announced on 31st March 2003 with the specific objective of accelerating the incremental growth in exports and to facilitate India emerging as a major base for sourcing different products and services for the rest of the world. It was recognised that status holders would continue playing a significant and increasing role for boosting exports particularly from the small-scale sector, as most of the small scale units would not be in a position to directly access the international market. In view of this, duty free import entitlement @ 10% of the incremental growth in value of exports was allowed, subject to the condition of eligibility on actual user condition, which could be passed on to supporting/associate manufacturers/job worker for ultimate production. Since the Scheme was intended to be a specific incentive for fast growing status holders, the benefits would be available w.e.f 1st April 2004.

Being a new initiative, a large number of representations have been received from Trade Associations/ Export Promotion Councils as well as the individual exporters seeking clarifications on various points relating to the implementation of the Scheme. At the same time, Government has received reports that some Status Holders are trying to increase their export turnover by taking credits for the export of others without putting any significant efforts in increasing exports. Such diversion/enhancement of exports merely to increase benefits under the Scheme in this manner would not lead to the intended objectives of incremental growth in exports. Such transactions amount to misuse of the Scheme. In view of this, on both these counts it has become essential to lay down specific norms for the implementation of the Scheme.

In the said Export and Import Policy,-

In Chapter-3, in paragraph 3.7.2.1., after sub-paragraph (vii), the following notes shall be inserted, namely:-

"Note 1.- For the purpose of calculating the value of exports, the following exports shall not be taken into account, namely:-

- (i) Re-export of imported goods or exports made through transshipment;
- (ii) Export turnover of units operating under SEZ/EOU/EHTP/STPI Schemes or products manufactured by them and exported through DTA units;
- (iii) Deemed exports (even when payments are received in Free Foreign Exchange) and payment from EEFC account
- (iv) Service exports
- (v) Supplies made by one status holder to another status holder;
- (vi) Export performance made by one status holder on behalf of other status holder will not be eligible for entitlement under the scheme.
- (vii) Supplies made or export performance effected by a non-status holder (Merchant exporter/Manufacturer with any export performance in 2003-04) to a status holder if the applicant as well as the non status holder have less than 25 per cent incremental growth over their respective previous years direct export turnover.

- (viii) The exports made by an applicant within a group and the group to which it belongs has individually less than 25 per cent incremental growth of export.

Note—2.— The incremental growth of exports by an exporter shall not, directly or indirectly, be transferred to any other exporters.”

Note-3 - Government reserves the right in public interest, to specify the export products, which shall not be eligible for calculation of incremental growth/ entitlement. Similarly, the government may also notify the list of goods, which shall not be allowed for imports under the scheme.

Note-4 — These guidelines will be applicable to the exports made on or after 1.04.2003.

Note-5 - The entitlement will be in terms of duty credit.

6. The sub paragraph 3 of paragraph 3.8 pertaining to the “duty free credit entitlement for service providers” shall be amended to read as under:

Service provider (other than hotels) shall be entitled to duty free imports equivalent to 10% of the average foreign exchange earned by them in preceding three licensing years. However, hotels (one star and above), heritage hotels, stand-alone restaurants approved by Department of Tourism, Govt. of India and other service providers in tourism sector registered with Department of Tourism, Govt. of India shall be entitled for duty free imports equivalent to 5% of the average foreign exchange earned by them in preceding three licensing years. For one & two star hotels and stand- alone restaurants, the foreign exchange earned through international credit cards only shall be taken into account for the entitlement under the scheme. The duty free entitlement shall be used for import of any capital good including spares, office equipment(s) & professional equipment(s), office furniture(s) & consumables. However agriculture, dairy products, motor cars, sports utility vehicles and all purpose vehicles would not be allowed to be imported against this entitlement .

The entitlement and the goods shall be non transferable and would be available only to those service providers, who have a total foreign exchange earning of over Rs.30 Lakhs in the preceding one/two/three licensing years.

7. Paragraph 4.1.6 pertaining to the Advance Licence is amended as under:-

The facility of advance licence shall also be available where all or some of the inputs are supplied free of cost to the exporter. In such cases, for calculation of value addition, the notional value of free of cost inputs alongwith value of other duty free inputs shall be taken into consideration. However, if all the inputs are supplied free of cost, the applicant shall have the flexibility to opt for the provisions of paragraph 4.2.7 of the Policy.

8. Paragraph 4.1.7 A pertaining to the Advance Licence for Annual Requirements" is amended as follows:-

Advance Licence can also be issued on the basis of annual requirement for physical exports, intermediate supplies or deemed exports.

Export House, Trading House, Star Trading Houses and Super Star Trading Houses shall be entitled for Advance Licence for annual requirement. However, if the status holders are holding the certificate as merchant exporter, they are also entitled to the Advance Licence for Annual Requirement provided they agree to the endorsement of the name(s) of the supporting manufacturer(s) on the relevant licence.

The entitlement under this scheme shall be upto 200% of the FOB/FOR value of export in the preceding licensing year. Such licence shall have positive value addition.

9. Paragraph 4.2.3 and 4.2.4 pertaining to Duty Free Replenishment Certificate is amended as follows:-

4.2.3: DFRC shall be issued only in respect of products covered under the Standard Input Output Norms as notified by DGFT. However, in respect of Standard Input Output Norms which are subject to "actual user" condition or where the input(s) is allowed with prior import condition or for import of fuel under the general norms, DFRC shall be issued with actual user condition for these inputs.

In cases where Standard Input Output Norms allow import of Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo Ephedrine , DFRC shall be issued provided these items are specifically deleted from the list of import items.

4.2.4: DFRC shall be issued for import of inputs as per SION as indicated in the shipping bills. The validity of such licences shall be 18 months. DFRC and or the material(s) imported against it shall be freely transferable. However, DFRC with actual user condition or the material(s) imported against it shall not be transferable.

10. Paragraph 4.2.7 is amended as under:

4.2.7: Import of goods, including those mentioned as restricted in ITC(HS) but excluding prohibited items, supplied free of cost, may be permitted for the purpose of jobbing without a licence/certificate/ permission as per the terms of notification issued by Department of Revenue from time to time.

Similarly, import of goods for carrying out repairs, re-conditioning, re-engineering, testing etc. shall be allowed as per the terms and conditions of the Customs notification even though the goods may be restricted for imports under the Exim Policy/ITC(HS) Classification of Imports and Exports Book.

11. The last sentence of paragraph 4.3.5 stands deleted.

12. The following sub paragraph is inserted at the end of paragraph 5.1 pertaining to “EPCG Scheme”

Spare refractories, catalyst and consumable for the existing plant and machinery may also be imported under the EPCG scheme. However, import of motor cars, sports utility vehicles/ all purpose vehicles shall be allowed only to hotels, travel agents, tour operators or tour transport operators whose foreign exchange earning in current licencing year or preceding 1/2/3 licencing years is Rs 1.5 crores.

13. Paragraph 5.1 A is amended to read as under:-

5.1 A Spares, spare refractories, catalyst & consumable for the existing plant and machinery may also be imported under the EPCG Scheme subject to an export obligation equivalent to 8 times of duty saved to be fulfilled over a period of 8 years reckoned from the date of issuance of licence.

14. Para 5.4(i) pertaining to “Export Obligation” is amended as under:

(i)The export obligation shall be fulfilled by the export of goods capable of being manufactured or produced by the use of the capital goods imported under the scheme. The export obligation may also be fulfilled by the export of same goods, for which EPCG licence has been obtained, manufactured or produced in different manufacturing units of the licence holder/specify supporting manufacturer (s)/ vendor(s). The export obligation under the scheme shall be, over and above, the average level of exports achieved by him in the preceding three licensing years for same and similar products except for categories mentioned in Handbook (Vol.1). Alternatively, export obligation may also be fulfilled by exports of other goods manufactured or service provided by the same firm/company or group company which has the EPCG licence. However, in such cases, the additional export obligation imposed under EPCG scheme shall be over and above the average exports achieved by the unit/company/group company in preceding three years for the substitute products/services.

The licensee can also opt for the re-fixation of the balance export obligation based on the 8 times of the duty saved amount for the CIF value in proportion to the balance Export obligation under the scheme.

The aforesaid facilities shall only be available to manufacturer exporters/ service provider on all the licences where export obligation period including extended export obligation period valid on the date of application . In this regard, exports made only on or after submission of application for alternate item and/ or re-fixation of the export obligation based on duty saved amount will be taken into account for fulfillment of export obligation.

15. Paragraph 6.6(a) is amended as under:

On approval, a Letter of Permission (LOP)/Letter of Intent (LOI) shall be issued by the Development Commissioner to EOU/EHTP/STP unit. The LOP shall have an initial validity of 3 years for commencement of production. Its validity may be extended by another 3 years, beyond initial validity, by the competent authority. However proposals approved prior to 1.4.2002 shall be considered on case to case

basis by the BOA beyond six years. Standard Format for LOP extension is given in Appendix 14-IMM.

16. Paragraph 6.7(a) is amended as under:

Only project having a minimum investment of Rs.1 crore and above in building, plant and machinery shall be considered for establishment under EOU scheme. Minimum investment should take place on coming into production of the unit. (This shall, however, not apply to existing units and units in EHTP/STP/ handicrafts/ agriculture/ floriculture/ aqua-culture/ animal husbandry/ information technology, services and such other sectors as may be decided by the BOA).

Applications for setting up of units under EOU scheme other than proposals for setting up of unit in the services sector (except R&D , software and IT enabled services, or any other service activity as may be delegated by the BOA), shall be approved or rejected by the Units Approval Committee within 15 days as per the criteria indicated in Appendix 14-I of Handbook (Vol-I).

17. In paragraph 7.7(a), after the word “except”, in bracket, the word “ R & D,” shall be inserted.
18. Paragraph 7.11 (a) shall be substituted as under:

7.11(a) “SEZ units may transfer manufactured goods, including partly processed/semi-finished goods and services from one SEZ unit to another SEZ/EOU/EHTP/STP unit. However, trading units in SEZ may sell/transfer goods imported/procured from DTA to another SEZ/EOU/EHTP/STP unit.”

19. Sub-paragraph 8.2 (f) shall be substituted by the following:

Supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by a notification, permits the import of such goods at zero customs duty.

20. Paragraph 9.47(iv) is amended as follows:-

Supply of a ‘service’ in India relating to exports paid in free foreign exchange or in Indian Rupees, which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by RBI.

This issues in public interest.

[F. No. 01/94/180/Notification/AM 04/PC.-IV]

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.